पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में प्रदेश प्रथम स्थान पर

- 13500 उद्यमियों को पांच लाख से 10 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत
- आवेदन के सापेक्ष 98 प्रतिशत वितरण के साथ उप्र अव्वल

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाइयां लगाने के योगी सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। इसका ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं, दूसरे नंबर पर बिहार है।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा की अध्यक्षता में शनिवार को रेशम निदेशालय में उद्यमियों के साथ उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 योजना की समीक्षा के लिए अप्रेजल समिति की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत अब तक एक हजार करोड़ रुपये की परियोजना के लिए 230 उद्यमियों को लेटर आफ कंफर्ट (एलओसी) जारी किया गया है। इससे एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। एक लाख किसानों की उपज का प्रसंस्करण किया जा रहा है। देश में इस योजना के माध्यम से सबसे अधिक 10 करोड़ रुपये की अनुदान धनराशि उत्तर प्रदेश उपलब्ध करा रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएम एफएमई) योजना में अब तक 13500 उद्यमियों को पांच लाख से 10 लाख रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उत्तर प्रदेश में आवेदन के सापेक्ष अनुदान का वितरण 98 प्रतिशत हुआ है, जबकि देश का औसत 50 प्रतिशत है। बैठक में मैक्रोनी, पास्ता, टोमैटो सास, मल्टीग्रेन फ्लोर मिल व राइस मिल से संबंधित आवेदनों को अप्रेजल समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने उपयुक्त पाए गये प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने पर सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री के सलाहकार डा. केवी राजू ने इस क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश, किसानों से कच्चे माल क्रय करने से संबंधित अनुबंध, रोजगार सृजन की अपेक्षा की। वहीं, आलू का उत्पादन व निर्यात बढ़ाने के संबंध में भी बैठक हुई। प्रसंस्करण योग्य आलू की प्रजातियों के उत्पादन में 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आलू उत्पादन में गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज को अपनाये जाने पर बल दिया गया। इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स कोलकाता की प्रतिनिधि मधुपर्णा भौमिक ने अगले साल 13 व 14 फरवरी को लखनऊ में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आलू एक्सपो आयोजित कराने का प्रस्ताव दिया।

उप्र की राजनीति, सरकार और अपराध संबंधित अन्य खबरें www.jagran.com पर पढ़ें